Title : Regulatory authority for airlines to oversee the functioning of airlines.

श्री विलास मुत्तेमवार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वह घरेलू एयरलाइंस द्वारा जो जनता के पैसों की लूट हो रही है, उस तरफ है। उस लूट में इस हाउस में बैठे हुए सभी सांसद महोदयों के पैसे की भी लूट हो रही है। वह इस तरह कि ये घरेलू एयरलाइंस वक्त-वक्त पर अनेक स्कीम्स जाहिर करती हैं और उसके तहत जब कोई बुकिंग होती है और किसी कारणवश अगर वे नहीं जा सके तो उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। इस तरह मैं समझता हूं कि यह कोई ठीक बात नहीं है। यह करने के लिए एयरलाइंस को अधिकार भी नहीं दिये गये हैं। यह किसी कायदे के अन्तर्गत नहीं होता। इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। आप जानती हैं कि अब जो एयरलाइंस में एक बढ़ावा आया है तो लोग उसमें जाना चाहते हैं। कई नई स्कीमें आई हैं, लेकिन लोग बुकिंग करते हैं और अगर कहीं जा नहीं सके तो उनके पैसे वापस नहीं होते। मैं समझता हूं कि यह व्यापार का ठीक तरीका नहीं है। अगर विदेशी एयरलाइंस है तो विदेशी एयरलाइंस में पैसेंजर का किसी कारणवश नहीं जाना हुआ तो उसके पैसे वापस मिलते हैं, लेकिन देसी, घरेलू एयरलाइंस में यह पैसे वापस नहीं होते। इसका कोई हिसाब भी नहीं है और कोई एकाउण्टेबिलिटी भी नहीं है कि ये पैसे हमने क्यों लिए। फिर कहते हैं कि एयरलाइंस को बड़ा घाटा हो रहा है।

मैं समझता हूं कि यह बड़ी समस्या है। हम एम.पीज़. को भी 34 बार एयरलाइंस में जाने का मौका मिलता है और कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि अपने पैसे से उनको जाना पड़ता है। अगर यहां पार्लियामेंट का प्रोग्राम बदल जाये, व्हिप आ जाये तो उनको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है और नो शो के तहत उनके पूरे पैसे जाते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, यह ठीक व्यापार का तरीका भी नहीं है। इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर नियंत्रण लगे और उनसे पूछा जाये कि आप पैसे वापस क्यों नहीं करते।

दूसरे, ईंधन और एयरपोर्ट की अवसंरचना की कीमत बढ़ती है, अगर एयरपोर्ट पर डैवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए उन पैसेंजर्स से एयरलाइंस आपस में मिलकर किराया तय करती हैं और उनसे एयरपोर्ट का डैवलपमेंट टैक्स वसूल करती हैं। मैं समझता हूं कि यह भी कहीं नहीं है। दुनिया में कई जगह नये एयरपोर्ट बने, लेकिन वहां इस प्रकार से डैवलपमेंट फीस वसूल नहीं की गई। ईवन इस क्षेत्र के हमारे हिन्दुस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि यह अनएथीकल है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अभी इन सारे एयरपोर्ट्स पर सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। वहां डैवलपमेंट चल रहा है और जो वहां सुविधाएं प्रदान की हैं तो वे बाजार से बहुत ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। अगर कोई रैस्टोरेंट वहां खुला है तो गांव में अगर इडली दो रुपये या पांच रुपये की मिलती है तो वहां एयरपोर्ट पर वह इडली 100 रुपये पर प्लेट मिलती है और सांभर वड़ा 150 रुपये पर प्लेट मिलता है। उसके पीछे यह आर्ग्यूमेंट है कि एयरपोर्ट में ज्यादा पैसे उनके लगते हैं, उनको ज्यादा किराया देना पड़ता है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि सरकार उस स्थिति में सुधार के लिए एयरक्राफ्ट नियम 37 के नियम 135 में बदलाव के द्वारा आदेश जारी करे, ताकि एयरलाइंस यात्री किराये के सम्बन्ध में कुछ नियमों को मानें।

परंतु कड़ी निगरानी के अभाव में एयरलाइंस इन नियमों को नहीं मानती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि एयरलाइंस के संचालन की देखरेख के लिए, किराये के निर्धारण के लिए और पैसेंजर्स के पैसों की लूट रोकने के लिए एक विनियामक प्राधिकरण नियुक्त किया जाए, ताकि यात्रियों को किसी तरह की हानि न हो।